बरुण मित्रा भा.प्र.से.
Barun Mitra, IAS

सचिव
न्याय विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
SECRETARY
DEPARTMENT OF JUSTICE
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
GOVERNMENT OF INDIA

अर्ध शासकीय पत्रांक 15011/35/2021-न्याय (एयू) दिनांक 16 जुलाई, 2021

मैं आपको न्याय विभाग से संबंधित जून, 2021 माह की महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराना चाहूँगा ।

1. उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दिनांक 10.06.2021 की अधिसूचना के माध्यम से की गई।

2. उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति:

दिनांक 22.06.2021 और दिनांक 28.06.2021 की अधिसूचना के माध्यम से क्रमशः इलाहाबाद उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में दो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।

3. उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति:

दिनांक 18.06.2021 की अधिसूचना के माध्यम से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में छह (06) स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।

4. उच्च न्यायालयों में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति:

बॉम्बे उच्च न्यायालयों में (04) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में (01), गौहाटी उच्च न्यायालय में (01) और केरल उच्च न्यायालय में (01) अर्थात कुल सात (07) अपर न्यायाधीश क्रमशः दिनांक

23.06.2021, 25.06.2021, 18.06.2021 और 23.06.2021 की अधिसूचना के माध्यम से नियुक्ति किए गए ।

5. ई-कोर्ट परियोजना और व्यवसाय करने में आसानी :

- मॉडल नियमों को अंतिम रूप देने की दिशा में एक कदम के रूप में आम जनता के विचार जानने के लिए लाइव-स्ट्रीमिंग और अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर तैयार किए गए मसौदा नियमों को वेबसाइट (https://www.mygov.in) पर रखा गया है ।
- अनुबंध व्यवस्था के शीघ्र कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, देश भर के वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए केस सूचना सॉफ्टवेयर में अब एक नई सुविधा शामिल की गई है, जिसके तहत वाणिज्यिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को रंग संकेतकों के माध्यम से 3 स्थगन स्थिति के बारे में सचेत किया जा रहा है : -

➢ हरा: यह दर्शाता है कि मामला एक ही चरण में 3 बार से कम समय के लिए सूचीबद्ध है।
➢ नारंगी: यह दर्शाता है कि मामला 3 से 6 बार के बीच एक ही चरण में सूचीबद्ध है।
➢ लाल: यह दर्शाता है कि मामला 6 बार से अधिक एक ही चरण पर सूचीबद्ध है।

इससे न्यायाधीशों को उन मामलों को प्राथमिकता देने और निर्णय लेने में सहायता मिलेगी जो अधिकतम 3 स्थगन नियमों की सीमा पार कर चुके हैं ।

- न्यायिक अधिकारियों के लिए 8 इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल के साथ JustIs मोबाइल ऐप का आईओएस संस्करण लॉन्च किया गया है। IoS और एंड्रॉइड संस्करणों में JustIs ऐप इंस्टॉलेशन पर चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका और JustIs मोबाइल ऐप के माध्यम से कोर्ट प्रबंधन के लिए एक उपयोगकर्ता गाइड भी बनाया गया है ।

- विकलांग व्यक्तियों के लिए अदालत की वेबसाइटों को सुलभ बनाने के लिए अब सभी उच्च न्यायालय की वेबसाइटों पर सुलभ दृश्य और ऑडियो कैप्चा उपलब्ध कराया गया है।

- डिजिटलीकरण पहल पर, केरल उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी 2021 को सभी वाणिज्यिक न्यायालयों में एनआईसी द्वारा विकसित ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया। एक सुरक्षित वाई-फ़ाई परियोजना; राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक समन ट्रैकिंग परियोजना और जिला न्यायपालिका के लिए सीआईएस सॉफ्टवेयर और भूमि रिकॉर्ड के एकीकरण का उद्घाटन 14 जून 2021 को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में किया गया ।

- कर्नाटक उच्च न्यायालय की धाखाड़ पीठ में एक नई जस्टिस क्लॉक (न्याय घड़ी) चालू की गई है । इस प्रकार, 20 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायालय परिसरों में 29 न्याय घड़ियाँ स्थापित की गई हैं ।

6. टेली लॉ:

86,167 व्यक्तियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई, जिसमें 26,973 महिलाएं, 25,650 अनुसूचित जाति, 17,122 अनुसूचित जनजाति और 24,654 अन्य पिछड़ा वर्ग लाभार्थी शामिल थे । 121 लाभार्थियों को कोविड-19 महामारी से संबंधित सलाह प्रदान की गई। 30 जून 2021 तक कुल 9,69,347 सलाह दी गई थी । 16 राज्यों के 95 जिलों में 74 प्रशिक्षण और अनुवर्ती सत्र आयोजित किए गए जिसमें 3129 राज्य स्तरीय समन्वयकों, ग्राम स्तरीय उद्यमियों और पैरा लीगल स्वयंसेवकों ने भाग लिया ।

7. न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विस):

माह के दौरान 197 नए वकीलों ने न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कराया । कुल 2936 वकीलों ने न्याय बंधु के तहत पंजीकरण कराया है । 25 जून 2021 को 100 न्याय बंधु पैनल वकीलों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

8. पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में न्याय तक पहुंच।

जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण (जेकेएलएसए) द्वारा जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में स्थापित 50 कानूनी सहायता क्लीनिक (एलएसी) के माध्यम से 4150 लोग लाभान्वित हुए । 22 ऑनलाइन कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा 1137 व्यक्तियों तक पहुंचा गया और 1859 व्यक्तियों को कोविड-19 राहत सेवाएं प्रदान की गईं ।

9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा):

नालसा ने भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री यूयू ललित और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य विधिक प्राधिकरणों और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों के साथ 14-18 जून, 2021 तक क्षेत्रीय परामर्श वर्चुअल स्वरूप में आयोजित किया गया ।

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया । शिशु परियोजना के तहत चिन्हित बच्चों को प्रायोजन योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया ।

10. एसीसी निर्देशों का अनुपालन न करना:

शून्य

भवदीय,

हस्ताक्षर/-
(बरुण मित्रा)

श्री राजीव गौबा
कैबिनेट सचिव,
कैबिनेट सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।

प्रति:

माननीय विधि एवं न्यायमंत्री के निजी सचिव, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

(बरुण मित्रा)